लोकप्रिय बनाने के लिए अनुदान की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश में 150 रु० प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा पर गेहूं के बीजों के वितरण पर राजसहायता देने हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुपालन में राज्य सरकार ने कृषि और सहकारिता को यह अनुरोध किया था कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई राज सहायता के बोझ को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए । राज्य सरकार ने धान के बीजों के मिनिकिटों का वितरण करने के लिए और धान के बीजों को रियायती दरों पर किसानों को सप्लाई करने के लिए भी अनुदान सहायता मांगी थी।

(ख) मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों के वितरण पर राज सहायता हेतु सिफारिश के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश में खेती की कुल लागत में बीजों की लागत का प्रतिशत पंजाब और हरियाणा राज्यों में खेती की कुल लागत में बीज की लागत के प्रतिशत से अधिक थी ।

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खेती की लागत का ब्यौरा आयोग से प्राप्त किया गया था और वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए मध्य प्रदेश , पंजाब और हरियाणा में खेती की लागत का विश्लेषण किया गया था । विश्लेषण से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की लागत में बीजों की लागत उतनी ही थी जितनी कि हरियाणा और पंजाब के मामले में यह सीमांततः कम थी परन्तु यह अन्तर कोई विशेष नहीं था । दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मामले में उर्वरक का उपयोग काफी कम पाया गया और इस कारण से मुख्यतः मध्य प्रदेश में खेती की कुल लागत की प्रतिशतता में प्रति हैक्टायर बीजों के उपयोग पर व्यय अधिक बैठता है । तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृषि आदानों के वैज्ञानिक प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि करके मध्य प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है । चूंकि बीजों की लागत पर राज्य सहायता उपलब्ध करा कर इस प्रयोजन को प्राप्त नहीं किया जा सका, अतः यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों पर राज सहायता उपलब्ध न कराई जाए ।

तथापि राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि राज्य में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक सघन क्षेत्र-विशेष गेहूं विकास कार्यक्रम बनाया जाए ।

जहां तक धान का संबंध है । पूर्वी मध्य प्रदेश के 40 चुने हुए जिलों में धान के बीजों के मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण करने तथा धान के बीजों के वितरण पर राज सहायता देने हेतु 126 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । इसे केन्द्र और राज्य के द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा । यह चावल मिनिकिट एवं सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम को केन्द्रीय धान की योजना के चावल के मिनिकिट के निःशुल्क वितरण हेतु मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई जा रही 100 प्रतिशत सहायता के अतिरिक्त है । इस योजना के तहत वर्ष 1985-86 के लिए मध्य प्रदेश हेतु 30.00 लाख रुपए की राशि सिफारिश की गई है ।

*2007. SHRI SUKOMAL SEN; INFOR MATION AND BR

(a) . tern Newspapers Society mac representation for reconsideration of the Directorate of Audio Visual Publicity rates ;

(b) if so, what action Govern ment have taken in this matter ; and

(c) if no action has been taken, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V.N. GADGIL) : (a) Yes, Sir.

(b) Gov .as already decided to. enhance Directorate of Advertising and Visual Publicity rates by 30 per cent with effect from the 1st September, 1985.

(c) Docs not arise.

Sone Canal Modernisation Scheme

. 2008. SHRI SURAJ PRASAD: SHRI INDRADEEP SINHA*:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sone Canal Modernisation Scheme has been submitted to the World Bank ;

(b)whether it is also a fact that the Bihar Government has not allocated sufficient fund in the Seventh Five Year Plan for. modernisation;

(c) it is a fact that the World Bank is not appraising the scheme due to insufficient allocation of funds ;

(d) v it is a fact that the Sone Canal system has become hun dred years old incapable for rendering any service; and

(e) if so, what steps have been taken to_ expedite the scheme ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) The Sone Canal Modernisation Scheme has been posed to the World Bank and has been included in the long term pipeline. However, further processing is contingent on resolving various technical and financial issues. The Government of Bihar has only made a token provision for the' project in the Seventh Five Year Plan.

(d) and (e) Sone Canal System is 100 years old and has naturally become less efficient and therefore, a scheme for modernisation of the Sone System has been submitted by the State Government for technical approval of the Planning Commission Phase-I of the scheme has also been approved by the Planning Commission.

Sugarcane Arrears

2009. SHRI SURAJ PRASAD: SHRI INDRADEEP SINHA :

Will the Minister of POOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) what steps are being taken by Government to clear arrears of prices of sugarcane ; and

(b) whether Government propose to insist on the sugar mill owners to pay interest on the arrears ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) Ensuring payment of cane price arrears is the direct responsibility of the State Governments, who have the necessary field organistions and powers to enforce such payments. The Central Government monitors the position and has been advising State Governents, from time to time, for expeditious clearance of cane price arrears.

The Central Government, on its part, has been taking steps aimed at improving the liquidity of the industry